1	2	3	4
Manipur	51	1.22	1.59
Nagaland	9	0.31	0.14
Orissa	114	3.13	1.97
Punjab	3	0.04	0.0050
Rajasthan	35	1.15	0.89
Tamil Nadu	86	2.23	2.10
Tripura	1	0.03	0.00
Uttar Pradesh	358	8.70	5.97
West Bengal	278	9.47	6.41
Mizoram	..	0.00	0.21
Chandigarh	2	0.09	0.00
Meghalaya	0	0.00	0.01
Pondicherry	..	0.00	0.0028
Goa Daman	..	0.00	0.0028
TOTAL	1607	45.80	36.70

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में गरीबीरेखा से नीचे रहने वाले लोग

1651. श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ोदरा और पंच महल जिलों के आदिवासी क्षेत्रों म गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनके लिये बनाये गये गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई समीक्षा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों से लाभांवित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) इन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1991 के दौरान कराये गये गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के सर्वेक्षण के दौरान गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है:—

गुजरात

		गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों की संख्या
1	सूरत	145276
2	भड़ौच	167997
3	बड़ोदरा	171285
4	पंचमहल	355084

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना गुजरात सहित संपूर्ण देश में सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे दो प्रमुख गरीबी निवारण कार्यक्रम हैं । प्रभावी कार्यान्वयन के लिये इन कार्यक्रमों की केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत रूप से समीक्षा की जाती है । केन्द्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों के वित्तीय और भौतिक निष्पादन की समीक्षा राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत की जाती है । इसके अलावा, समय-समय पर इन कार्यक्रमों की समीक्षा राज्य सचिवों के साथ तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के परियोजना निदेशकों के लिये आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों की मार्फत इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और आवश्यक उपचारी उपाय करने के लिये की जाती है । इन कार्यक्रमों की गुणात्मक निगरानी के लिये सरकार ने क्षेत्र अधिकारियों की एक योजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्य चुने हुये जिलों/राज्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता एवं भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर विशेष बल देते हुये मुख्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना है । राज्य स्तर पर योजनाओं की समीक्षा राज्य स्तर समन्वय समितियों द्वारा भी की जाती है । इसके अलावा समय समय पर प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन भी इन कार्यक्रमों की गहराई से समीक्षा करने के लिये कराये जाते हैं । इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिये आवश्यक उपचारी उपाय किये जाते हैं ।

(ग) इन कार्यक्रमों की मार्फत लाभांवित लोगों की संख्या केन्द्र स्तर पर जिला-वार नहीं रखी जाती है । तथापि, गुजरात राज्य के लिये राज्य स्तर सूचना निम्नलिखित है:—

क्रमांक	कार्यक्रम	लाभान्वित परिवार/सृजित रोजगार	अवधि 1994-95
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48682 (परिवारों की संख्या)	दिसम्बर, 94 तक
2.	जवाहर रोजगार योजना	123.92 (लाख श्रमदिन)	जनवरी, 95 तक
3.	गहन जवाहर रोजगार योजना	44.08 (लाख श्रमदिन)	जनवरी, 95 तक
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	15.93 (लाख श्रमदिन)	जनवरी, 95 तक

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना, गहन जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मार्फत केन्द्र सरकार ने कई विशिष्ट प्रयास किए है । इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराना है । उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना को 1993-94 के दौरान देश के उन 120 चुने हुए पिछड़े जिलों में गहन बनाया गया है, जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की अधिकता है । इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जिन्हें रोजगार चाहिए, को गैर

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना गुजरात सहित संपूर्ण देश में सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे दो प्रमुख गरीबी निवारण कार्यक्रम हैं । प्रभावी कार्यान्वयन के लिये इन कार्यक्रमों की केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत रूप से समीक्षा की जाती है । केन्द्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों के वित्तीय और भौतिक निष्पादन की समीक्षा राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत की जाती है । इसके अलावा, समय-समय पर इन कार्यक्रमों की समीक्षा राज्य सचिवों के साथ तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के परियोजना निदेशकों के लिये आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों की मार्फत इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और आवश्यक उपचारी उपाय करने के लिये की जाती है । इन कार्यक्रमों की गुणात्मक निगरानी के लिये सरकार ने क्षेत्र अधिकारियों की एक योजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्य चुने हुये जिलों/राज्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता एवं भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर विशेष बल देते हुये मुख्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना है । राज्य स्तर पर योजनाओं की समीक्षा राज्य स्तर समन्वय समितियों द्वारा भी की जाती है । इसके अलावा समय समय पर प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन भी इन कार्यक्रमों की गहराई से समीक्षा करने के लिये कराये जाते हैं । इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिये आवश्यक उपचारी उपाय किये जाते हैं ।

(ग) इन कार्यक्रमों की मार्फत लाभांवित लोगों की संख्या केन्द्र स्तर पर जिला-वार नहीं रखी जाती है । तथापि, गुजरात राज्य के लिये राज्य स्तर सूचना निम्नलिखित है:-

क्रमांक	कार्यक्रम	लाभान्वित परिवार/सृजित रोजगार	अवधि 1994-95
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48682 (परिवारों की संख्या)	दिसम्बर, 94 तक
2.	जवाहर रोजगार योजना	123.92 (लाख श्रमदिन)	जनवरी, 95 तक
3.	गहन जवाहर रोजगार योजना	44.08 (लाख श्रमदिन)	जनवरी, 95 तक
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	15.93 (लाख श्रमदिन)	जनवरी, 95 तक

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना, गहन जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मार्फत केन्द्र सरकार ने कई विशिष्ट प्रयास किए है । इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराना है । उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना को 1993-94 के दौरान देश के उन 120 चुने हुए पिछड़े जिलों में गहन बनाया गया है, जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की अधिकता है । इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जिन्हें रोजगार चाहिए, को गैर